(c) By giving a legal status to the Board it is hoped to improve the working of social welfare programmes. The Board is expected to enjoy a larger measure of autonomy in day-to-day working, with freedom to experiment with new ideas and schemes and thus secure the active participation of a large number of voluntary social workers. Besides the legal status will contribute to the growth of public accountability and responsibility.

नल कूपों को चलाने के लिये बिजली

1234. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों को चलाने के लिए कितने प्रतिशत बिजली की सप्लाई की जा रही है ;

(ख) नये बीजों, खाद तथा खेती के तरीकों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि देश में नल-कूपों की ज्यादा से ज्यादा कितनी आवश्यकता है और उनको चलाने के लिए कितने किलोवाट बिजली की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी कोई दीर्घकालीन वृहत् योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत देश में उन सभी नलकूपों को जिनके लगाये जाने की सम्भावना है, बिजली दी जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) नलकूपों और पम्पों को चलाने के लिए काम में लाई गई ऊर्जा के सम्बन्ध में पृथक-पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु 1965-66 के दौरान देश में बेची गई कुल ऊर्जा का लगभग 6.9 प्रतिशत भाग कृषि सम्बन्धी कामों में लगाया गया ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित का निर्माण परिकल्पित है :—

1. लगभग 5000 अतिरिक्त सरकारी नलकूप, जिनमें से लगभग 4000 बिजली से चलाए जाएंगे ।
2. लगभग 1 लाख गैर-सरकारी नल-कूप, जिनमें से लगभग 50 लाख बिजली से चलाए जाएंगे ।
3. खोदे गये कूपों और सरिताओं आदि में लगभग 8 लाख पम्पों का लगाना ।

इन नल-कूपों/पम्पों को ऊर्जित करने का काम मुख्यतः ग्राम विद्युतन कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाएगा । इस उद्देश्य के लिये अधिकांश राज्यों में बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के आगे की अवधि के लिए नल-कूपों के निर्माण। पम्पों के प्रतिष्ठापन की कोई ठीक-ठीक योजना नहीं बनाई गई है। परन्तु भू-जल के सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान के काम में चौथी योजना के दौरान तेजी लाई जा रही है और अगला विकास कार्यक्रम इन सर्वेक्षणों के परिणामों पर और कुछ हद तक चौथी योजना के दौरान हुई कार्यगति पर आधारित होगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली लगाना

1235. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को गांवों में बिजली लगाने तथा नलकूपों को चलाने के

लिये बिजली देने के लिये कुल कितनी सहायता दी है ; और

(ख) उस सहायता से कितने गांवों तथा नलकूपों के लिये बिजली की व्यवस्था की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) इस उद्देश्य के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले तीन वर्षों में दी गई कुल केन्द्रीय ऋण सहायता वर्ष-वार नीचे बताई जाती है :—

वर्ष	केन्द्रीय ऋण सहायता लाख रु० में
1964-65 . .	265.00
1965-66 . .	591.79
1966-67 . .	1529.97
कुल .	2386.76

(ख) इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की सलाह ली गई थी जिन्होंने निम्नलिखित जानकारी भेजी है :—

वर्ष	जिन बस्तियों में बिजली दी गई उनकी संख्या	गैर-सरकारी ऊंचित नल-कूपों और पंपों की संख्या
1964-65	2152	(उपलब्ध नहीं) परन्तु 31-3-65 तक 4554 गैर-सरकारी नल-कूपों को ऊंचित किया गया।
1965-66	671	4729
1966-67	110	19619
कुल	2,933	29902

गोरखपुर उर्वरक कारखाने में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी

1226. डा० महादेव प्रसाद : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर उर्वरक कारखाने में इस समय काम कर रहे पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) उपरोक्त श्रेणियों में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन, खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

पद की श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के कर्मचारी
i	95	शून्य
ii	41	1
iii	653	9
iv	366	38
	1155	47